नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 250
दि. 13.06.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

खाने की थाली में बढ़ता खतरा! मैगी, खजूर और फास्ट फूड पर उठे सवाल, एफएसएसएआई ने कंपनियों से मांगा जवाब

नई दिल्ली। देश में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता विश्वास को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो और उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कई बड़ी खाद्य कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मैगी के पैकेट में कथित रूप से कीड़े मिलने, खजूर आधारित उत्पाद में कीड़ों की शिकायत और एक प्रमुख फास्ट फूड आउटलेट में गंदगी संबंधी आरोपों ने खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएसएआई ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है और उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

देश में पैकेज्ड फूड और रेडी-टू-ईट उत्पादों की बढ़ती खपत के बीच इस तरह की शिकायतों ने लाखों उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य उत्पादों में गुणवत्ता से जुड़ी छोटी सी चूक भी लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि नियामक एजेंसियां अब सोशल मीडिया पर सामने आने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लेकर तत्काल जांच की प्रक्रिया शुरू कर रही हैं।

सबसे अधिक चर्चा उस वीडियो को लेकर हो रही है जिसमें लोकप्रिय इंस्टेंट नूडल्स ब्रांड मैगी के एक पैकेट में कथित तौर पर कीड़े दिखाई देने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए। वीडियो तेजी से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया, जिसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी।

एफएसएसएआई ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्राधिकरण ने कंपनी से यह जानकारी देने को कहा है कि संबंधित उत्पाद किस बैच का था, उसकी आपूर्ति श्रृंखला क्या थी और उत्पादन से लेकर बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया में किन-किन स्तरों पर गुणवत्ता जांच की गई थी। इसके अलावा कंपनी से यह भी

पूछा गया है कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो खराब उत्पादों को बाजार से हटाने के लिए क्या व्यवस्था मौजूद है और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पैकेज्ड उत्पाद में कीड़े या अन्य दूषित तत्वों की मौजूदगी कई कारणों से हो सकती है। इनमें उत्पादन प्रक्रिया में कमी, पैकेजिंग में दोष, भंडारण के दौरान खराब परिस्थितियां या वितरण श्रृंखला में लापरवाही शामिल हो सकती है। इसलिए जांच एजेंसियां केवल अंतिम उत्पाद ही नहीं बल्कि उसकी पूरी सप्लाई चेन की भी समीक्षा करती हैं।

इसी बीच एक और मामला सामने आया है जिसने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक उपभोक्ता ने दावा किया कि उसे ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट मिनट्स के माध्यम से प्राप्त एक खजूर आधारित उत्पाद में कीड़े मिले। शिकायत के साथ साझा की गई तस्वीरों और वीडियो ने तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उपभोक्ताओं ने सवाल उठाया कि यदि पैक्ड और ब्रांडेड उत्पादों में भी इस तरह की समस्याएं सामने आने लगें तो लोगों का भरोसा किस पर कायम रहेगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए एफएसएसएआई ने संबंधित कंपनी ओपन सीक्रेट को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने कंपनी से पूछा है कि शिकायत मिलने के बाद उसने तत्काल क्या कार्रवाई की, प्रभावित उत्पादों की जांच कैसे की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही कंपनी से यह भी कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो संदिग्ध बैच को बाजार से वापस लेने की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

विशेषज्ञों का कहना है कि सूखे मेवे और खजूर जैसे उत्पादों में यदि भंडारण और तापमान नियंत्रण का विशेष ध्यान न रखा जाए, तो उनमें कीट संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए ऐसे उत्पादों के उत्पादन, पैकेजिंग और स्टोरेज के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। खाद्य सुरक्षा से जुड़ा तीसरा मामला आंध्र प्रदेश के एलुरु स्थित एक केएफसी आउटलेट से संबंधित है। यहां सोशल मीडिया पर वायरल हुई शिकायतों में आरोप लगाया गया कि स्टोर में साफ-सफाई के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। आरोपों में खाद्य सामग्री के रखरखाव, कचरा प्रबंधन और कर्मचारियों की स्वच्छता से जुड़े कई मुद्दे शामिल बताए गए हैं। इन आरोपों के बाद एफएसएसएआई ने संबंधित कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है।

प्राधिकरण ने कंपनी से यह बताने को कहा है कि स्टोर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन-कौन से मानक अपनाए जाते हैं और शिकायतों में उठाए गए बिंदुओं पर क्या जांच की गई है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। केएफसी का संचालन करने वाली देवयानी इंटरनेशनल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह मामले की आंतरिक जांच कर रही है और नियामक एजेंसी को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी। इन तीनों मामलों ने एक बार फिर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया उपभोक्ताओं के लिए अपनी शिकायतें सामने रखने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। पहले जहां किसी शिकायत को संबंधित विभाग तक पहुंचने में काफी समय लगता था, वहीं अब कुछ ही घंटों में लाखों लोग किसी मुद्दे से अवगत हो जाते हैं और नियामक संस्थाओं पर कार्रवाई का दबाव बढ़ जाता है।

एफएसएसएआई द्वारा त्वरित कार्रवाई को उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी शिकायत की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होती है, लेकिन नियामक संस्था का समय रहते हस्तक्षेप करना उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। इससे कंपनियों पर भी गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों को और मजबूत करने का दबाव बनता है।

भारत में खाद्य उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। पैकेज्ड फूड, इंस्टेंट फूड, ऑनलाइन ग्रॉसरी और फास्ट फूड बाजार में करोड़ों उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। ऐसे में गुणवत्ता संबंधी एक छोटी घटना भी बड़े पैमाने पर विश्वास को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि खाद्य कंपनियों के लिए केवल उत्पाद बेचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक हर स्तर पर सुरक्षा और स्वच्छता के उच्चतम मानकों का पालन करना पड़ता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य सुरक्षा केवल सरकार या कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं की सतर्कता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी उत्पाद में गड़बड़ी दिखाई दे तो उसकी शिकायत संबंधित मंचों पर करना और प्रमाण उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

फिलहाल सभी संबंधित कंपनियों की नजरें एफएसएसएआई की जांच प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में कंपनियों के जवाब और जांच रिपोर्ट यह स्पष्ट करेंगे कि वायरल वीडियो और शिकायतों के पीछे वास्तविक स्थिति क्या थी। लेकिन इतना निश्चित है कि इन घटनाओं ने खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और उपभोक्ता विश्वास को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है। देश के करोड़ों उपभोक्ता अब यह जानना चाहते हैं कि उनकी थाली तक पहुंचने वाला भोजन वास्तव में कितना सुरक्षित है और उसकी गुणवत्ता की निगरानी कितनी प्रभावी ढंग से की जा रही है।

तमिलनाडु की राजनीति में दलबदल पर बड़ा एक्शन चार पूर्व विधायकों पर लटकी अयोग्यता की तलवार

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में दलबदल को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर द्वारा एआईएडीएमके छोड़कर तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) में शामिल हुए चार पूर्व विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दलबदल विरोधी कानून के तहत इन नेताओं को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राज्य की राजनीति में नए समीकरणों और संभावित राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा तेज हो गई है।

विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि एआईएडीएमके द्वारा दायर याचिका के आधार पर चारों पूर्व विधायकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। 9 जून को भेजे गए इन नोटिसों में संबंधित नेताओं से पूछा गया है कि उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। अध्यक्ष ने उन्हें जवाब देने के लिए सात दिनों का समय दिया है। यदि उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब एआईएडीएमके के चार विधायक—मरागथम कुमारवेल, एस. जयकुमार, पी. सत्यबामा और एसाक्की सुबाया—ने विधायक पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के भीतर सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कजगम का दामन थाम लिया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, इस्तीफा और नई पार्टी में शामिल होने के बीच का बेहद कम अंतराल ही इस मामले को कानूनी रूप से अधिक संवेदनशील बना रहा है।

इन चारों नेताओं का नाम उन 25 बागी विधायकों में भी शामिल था जिन्होंने 13 मई को विधानसभा में हुए विश्वास मत के दौरान पार्टी लाइन से हटकर टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया था। उस समय यह घटनाक्रम तमिलनाडु की राजनीति का सबसे चर्चित मुद्दा बन गया था। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कड़ी आलोचना की थी, जबकि बागी नेताओं ने अपने फैसले को जनहित और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप बताया था।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी व्हिप के विपरीत मतदान करना ही आगे चलकर इस पूरे विवाद की मुख्य वजह बना। भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कानून के तहत किसी भी विधायक या सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है यदि वह अपनी पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए मतदान करता है या स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।

विधानसभा अध्यक्ष प्रभाकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्णय विधानसभा के भीतर उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों और पत्राचार के आधार पर लिए जा रहे हैं तथा इनका बाहरी राजनीतिक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष का पद निष्पक्षता और संवैधानिक जिम्मेदारी का प्रतीक है तथा वह उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

इस घटनाक्रम का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया है। एआईएडीएमके द्वारा पहले 21 अन्य बागी विधायकों के खिलाफ भी अयोग्यता की मांग की गई थी, लेकिन बाद में पार्टी ने वह अनुरोध वापस ले लिया। इसके पीछे पार्टी के भीतर हुए समझौते को वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले समूह और एआईएडीएमके नेतृत्व के बीच हाल ही में सुलह हो गई थी, जिसके बाद अधिकांश बागी नेता फिर से पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए। सूत्रों के अनुसार, इस सुलह में पार्टी महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने असंतुष्ट नेताओं को संगठन में सम्मानजनक स्थान देने और पार्टी को एकजुट रखने की दिशा में प्रयास किए। इसके परिणामस्वरूप 21 विधायकों से जुड़ा विवाद शांत हो गया, लेकिन चार नेताओं का मामला अब भी विवाद का केंद्र बना हुआ है क्योंकि वे दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं।

कॉमेडी या संवेदनहीनता? मेडिकल छात्रा की टिप्पणी पर मचा बवाल, अस्पताल से पुलिस तक कार्रवाई तेज

मुंबई। मनोरंजन और अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं को लेकर देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस बार विवाद का केंद्र बनी हैं मुंबई के प्रतिष्ठित किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) अस्पताल की एक मेडिकल छात्रा, जिनकी स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान की गई टिप्पणी ने चिकित्सा जगत, सोशल मीडिया और आम जनता के बीच तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। मानव शवों के निजी अंगों को लेकर कथित तौर पर की गई टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद मामला केवल नैतिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अस्पताल प्रशासन, चिकित्सा संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रियता का विषय बन गया है। घटना ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मनोरंजन और हास्य के नाम पर उन मूल्यों की अनदेखी की जा सकती है, जिन पर चिकित्सा शिक्षा और मानव सम्मान की पूरी व्यवस्था आधारित है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया केवल वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें संवेदनशीलता, मानवीय गरिमा और नैतिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद प्रतिक्रिया केवल एक बयान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे चिकित्सा पेशे

की गरिमा से जोड़कर देखा जाने लगा। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब पुणे निवासी और केईएम अस्पताल में एमबीबीएस तृतीय वर्ष की छात्रा सेजल पवार एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में शामिल हुईं। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मेडिकल शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले पुरुष मानव शवों के निजी अंगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के लिए यह संभवतः हास्य का हिस्सा रहा हो, लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो व्यापक स्तर पर आलोचना शुरू हो गई। देखते ही देखते यह वीडियो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे मृत व्यक्तियों तथा अंगदान करने वाले परिवारों के सम्मान के खिलाफ बताया। चिकित्सा क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानव शव केवल शैक्षणिक सामग्री नहीं होते, बल्कि वे उन लोगों की अंतिम देन होते हैं जिन्होंने चिकित्सा शिक्षा और समाज के हित में अपना शरीर दान किया होता है। ऐसे में शवों को सम्मानपूर्वक देखना और उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार करना चिकित्सा प्रशिक्षण का मूल हिस्सा माना जाता है। यही वजह है कि इस टिप्पणी को केवल एक मजाक के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि चिकित्सा नैतिकता के संदर्भ में भी इसकी समीक्षा की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केईएम अस्पताल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया। समिति में हॉस्टल वार्डन एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रमुख डॉ. अनीता चालाक तथा मेडिसिन विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. श्रद्धा मोरे को शामिल किया गया है। समिति ने पूरे कार्यक्रम के लगभग एक घंटे के वीडियो फुटेज का अध्ययन किया है और घटना की परिस्थितियों की विस्तृत समीक्षा की है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि क्या छात्रा की टिप्पणी ने नेशनल मेडिकल कमीशन की सोशल मीडिया और पेशेवर आचरण संबंधी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। अस्पताल प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट डीन को सौंप सकती है। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन यह तय करेगा कि छात्रा के खिलाफ संस्थागत स्तर पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी छात्र या चिकित्सक का व्यवहार पेशे की गरिमा के विपरीत पाया जाता है, तो संस्थान उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठा सकते हैं। उधर, मामला केवल संस्थागत जांच तक सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी इस पूरे घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा, छात्रा सेजल पवार और कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में सभी संबंधित व्यक्तियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में सार्वजनिक मंचों पर दिए गए बयान अब केवल कार्यक्रम स्थल तक सीमित नहीं रहते। यदि कोई सामग्री व्यापक रूप से प्रसारित होती है और उससे सामाजिक या पेशेवर भावनाएं आहत होती हैं, तो उसके कानूनी परिणाम भी सामने आ सकते हैं।

ममता के गढ़ में सबसे बड़ी दरार! सांसदों-विधायकों की बगावत से बंगाल की राजनीति में भूचाल, टीएमसी के सामने अस्तित्व का संकट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक भूकंप के संकेत मिल रहे हैं। लंबे समय से राज्य की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकत मानी जाने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अब अपने ही घर में उठे असंतोष और बगावत की चुनौती का सामना कर रही है। पार्टी के भीतर जारी खींचतान अब खुले राजनीतिक विद्रोह का रूप लेती दिखाई दे रही है। हालिया घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि टीएमसी के भीतर मतभेद केवल संगठनात्मक असहमति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक समानांतर शक्ति केंद्र उभरने की कोशिश कर रहा है, जो पार्टी के भविष्य और पश्चिम बंगाल की राजनीति दोनों को नई दिशा दे सकता है।

राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब लोकसभा के 19 सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए एक पत्र की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि यह पत्र 18 मई को भेजा गया था, जिसमें अलग संसदीय गुट को मान्यता देने की मांग की गई थी। इस घटनाक्रम ने यह संकेत दिया कि पार्टी के भीतर असंतोष चुनावी झटके के तुरंत बाद ही शुरू हो गया

था। यदि यह दावा सही साबित होता है तो इसका अर्थ है कि शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देने की तैयारी काफी पहले से चल रही थी और अब वह निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है।

इससे पहले राज्य विधानसभा में भी बड़ा घटनाक्रम सामने आया था। पार्टी के 58 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने अलग गुट को मान्यता देने की मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस मांग को स्वीकार किए जाने के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि एक ही समय में बड़ी संख्या में विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाते हैं तो यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए गंभीर संकट का संकेत होता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बागी खेमे में कई ऐसे चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं जो टीएमसी की पहचान और लोकप्रियता का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इनमें खेल, फिल्म और राजनीति से जुड़े चर्चित नाम शामिल हैं। यही कारण है कि इस बगावत को केवल संख्या का खेल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पार्टी के जनाधार और नेतृत्व की स्वीकार्यता से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम को और रोचक बनाने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 14 जून को दिल्ली पहुंचकर बागी सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। यह बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे आने वाली राजनीतिक रणनीति का आधार माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में होने वाली इस बैठक के बाद बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर अपनी ताकत और संख्या बल का प्रदर्शन कर सकते हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली में होने वाली यह बैठक पश्चिम बंगाल की राजनीति का भविष्य तय करने वाली साबित हो सकती है। यदि बागी सांसद संगठित रूप से अलग पहचान की मांग करते हैं और उन्हें संसदीय मान्यता मिल जाती है तो यह टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा। दूसरी ओर यदि पार्टी नेतृत्व इस संकट को संभालने में सफल रहता है तो यह उसके लिए राहत की बात होगी।

बागी खेमे के नेताओं के बयान भी संकेत दे रहे हैं कि अब पीछे लौटने की संभावना बेहद कम है। सांसद अरूप चक्रवर्ती ने दावा किया है कि लगभग 20 सांसद उनके गुट के साथ हैं और उनका उद्देश्य पार्टी को नए स्वरूप में पुनर्गठित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका समूह राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम करना चाहता है। इस बयान को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें पहली बार खुलकर नई राजनीतिक दिशा का संकेत दिया गया है।

चक्रवर्ती के बयान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बागी गुट केवल विरोध दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह भविष्य की राजनीतिक संरचना तैयार करने की सोच रहा है। उन्होंने जिस प्रकार 'डबल इंजन सरकार' की अवधारणा का समर्थन किया है, उससे राजनीतिक पर्यवेक्षक यह अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा और बागी गुट के बीच किसी प्रकार की रणनीतिक समझ विकसित हो सकती है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक दशक से अधिक समय से टीएमसी राज्य की राजनीति का केंद्र बनी हुई है। ममता बनर्जी ने अपने संघर्ष, जनसंपर्क और राजनीतिक कौशल के दम पर पार्टी को एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति में बदल दिया था। लेकिन सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के बाद अक्सर राजनीतिक दलों के भीतर नेतृत्व, अवसर और संगठनात्मक संरचना को लेकर असंतोष बढ़ने लगता है। वर्तमान संकट को भी कई विश्लेषक उसी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े दल में जब वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों का एक बड़ा समूह एक साथ असंतोष व्यक्त करता है, तो यह केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मामला नहीं रह जाता। इसके पीछे संगठनात्मक निर्णयों, नेतृत्व शैली, टिकट वितरण, सत्ता संतुलन और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं जैसे कई कारण हो सकते हैं।

टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब अपने संगठन को एकजुट बनाए रखने की है। यदि बागी गुट अपनी ताकत बढ़ाने में सफल होता है तो इसका प्रभाव केवल संसद या विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर भी पड़ेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व को संगठनात्मक एकता बनाए रखने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। दूसरी ओर भाजपा और अन्य विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

सशक्तीकरण के दावे हकीकत भी बनें

यूं तो भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के तमाम दावे गाहे-बगाहे किए ही जाते हैं। आधी दुनिया को पूरा हक देने की बात होती है। किंतु-परंतु के बीच उन्हें जनप्रतिनिधि संस्थाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने पर प्रतिबद्धता जतायी जाती है। लेकिन इन दावों के बीच सामने आया एक कड़वा सच हमें वास्तविक स्थिति से रूबरू करा देता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में ग्रामीण इलाकों में हर चौथी और शहरी क्षेत्र में हर छठी महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती रही है। यह विडंबना ही है कि शहरों की तुलना में ज्यादा शांत व सुरक्षित माने जाने वाले ग्रामीण इलाकों में स्त्रियों को घरेलू एवं यौन हिंसा का ज्यादा सामना करना पड़ता है। वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के योगदान को राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें नेशन बिल्डर तक कह दिया। यहां तक कि घर और परिवार की देखभाल में गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कल्पित आर्थिक मूल्य का निर्धारण करते हुए उसे नजरअंदाज न करने की सलाह दी। यह विडंबना ही है कि जिन महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट नेशन बिल्डर बता रहा है, उन्हें हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आखिर महिला सशक्तीकरण के सारे विशेष प्रयास सिर्फ कागजों तक ही क्यों सिमट जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि महिलाओं की रक्षा-सुरक्षा हेतु तमाम विशेष कानून बनाये जाने के बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदलती है। इसमें दो राय नहीं कि समय-समय पर महिला उत्थान के लिये तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान चलाये जाते रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकासात्मक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जीवन के हर क्षेत्र में वे अपना आकाश तलाश रही हैं। विधायिका में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल सहमत नजर आते हैं। सवाल यही है कि जीवन व्यवहार में स्थिति क्यों नहीं बदलती।

देश के नीति-नियंताओं को इस गंभीर मुद्दे पर विचार करना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये तमाम विशेष कानून बनाये जाने के बावजूद क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में हर चौथी व शहरी क्षेत्र में हर छठी स्त्री को हिंसा व यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि घर से लेकर बाहर तक वे खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं? क्या कहीं इसमें पितृसत्ता प्रधान समाज की मानसिकता कारण है? दरअसल, आज लड़कियों व महिलाओं के खिलाफ हिंसा कई रूपों में मौजूद है। आजादी के सात दशक बाद भी हम दहेज के कलंक से मुक्त नहीं हो पाये हैं। हाल के दिनों में दहेज हत्या के कई बहुचर्चित मामले प्रकाश में आए। एक लड़की की पढ़ाई से लेकर शादी तक मां-बाप काफी खर्च करते हैं, फिर दहेज देने की जरूरत क्यों? छोटी-छोटी बातों में महिलाओं से मारपीट की खबरें आती हैं। वहीं अदिवासी व पिछड़े इलाकों में महिलाओं को डायन बताकर मारने की घटनाएं सामने आती हैं। हमारा समाज आज भी अंधविश्वासों और जादू-टोने के भय से मुक्त नहीं हुआ है। जिसके चलते महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आते हैं। सर्वेक्षण का यह तथ्य चौंकाता है कि 18 से 49 आयु वर्ग की विवाहिताओं में बाईस फीसदी को वैवाहिक जीवन में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा है। हालांकि, समय के साथ हिंसा के आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति चिंता पैदा करती है। जो किसी सभ्य समाज के माथे पर एक दाग की तरह ही है। हमारी व्यवस्था की विसंगतियां, पुरुष प्रधान सोच और हिंसा रोकने के लिये बनाए गए कानूनों के क्रियान्वयन में खामियां महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने में बाधक हैं। जो सामाजिक विसंगति की ओर इशारा करता है। यदि समय रहते कानून प्रवर्तन एजेंसियां संवेदनशील ढंग से कदम उठायें तो महिलाएं खुद को घर-बाहर सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर अवस्था के दौरान यौन-हिंसा का शिकार होने का प्रतिशत शहरों के मुकाबले अधिक होना, ग्रामीण समाज में विद्रूपताओं को दर्शाता है। जरूरी है कि ग्रामीण समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया जाए।

राजनीतिक सोच की गरीबी का त्रास झेलता पंजाब

> राज्य में बेरोजगारी और असमानता दूर करने हेतु संरचनात्मक समाधान पेश करने, जलवायु परिवर्तन प्रभावों और घटते भूजल स्तर को रोकने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती गुणवत्ता को सुधारने और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है।

पंजाब में पिछले कुछ सालों में राजनीति मुनाफा कमाने का एक ऐसा धंधा बन गया है, जिसमें लोगों के लिए काम करने की जगह व्यक्तिगत फायदे के लिए राजनीतिक दल बदली एक आम प्रक्रिया हो गई है। चुनाव जीतने के लिए किसी राजनीतिक प्रेरणा या पॉलिसी के बजाय पैसे, पावर और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल आम हो गया है। अपने नुमाइंदे चुनते समय, राजनीतिक पार्टियां उसकी राज्य में जलवायु परिवर्तन, संसाधन क्षरण, बिगड़ती शहरी सेवाओं, हेल्थ और एजुकेशन को सही दिशा देने के लिए लोगों के हित में एक ठोस पॉलिसी बनाने की क्षमता के बजाय चुनाव क्षेत्र में उसके परिवार के कंट्रोल और पैसे खर्च करने की उसकी क्षमता और सहमति को प्राथमिकता दे रही हैं।

आज़ादी के बाद से लंबे समय तक पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सत्ता की अदला-बदली करते रहे हैं, लेकिन 2022 से पॉलिटिकल पावर का कंट्रोल आम आदमी पार्टी के पास है; जबकि भविष्य में भाजपा राज्य की बागडोर संभालने के लिए बेचैन हो रही है। सरकार द्वारा पंजाब को आर्थिक कर्ज़ से आज़ाद करने और लोगों को रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं देने के लिए कोई पक्का प्रोग्राम बनाने के बजाय, राज्य में मुफ़्त आटा, दाल, मुफ़्त बिजली, मुफ़्त बस यात्रा, मुफ़्त तीर्थयात्रा और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मुफ़्त देने वगैरह का लालच देकर थोड़े समय की लोकप्रियता हासिल की जा रही है। टिकाऊ सुधारों के बजाय तुरंत चुनावी फ़ायदे को तरजीह दी जा रही है, लेकिन न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने से बचा जा रहा है। पंजाब के 'दस उंगलियों से काम करने और बांटकर खाने' वाले उसूल को कमज़ोर किया जा रहा है और लोगों को बेकार बनाया जा रहा है।

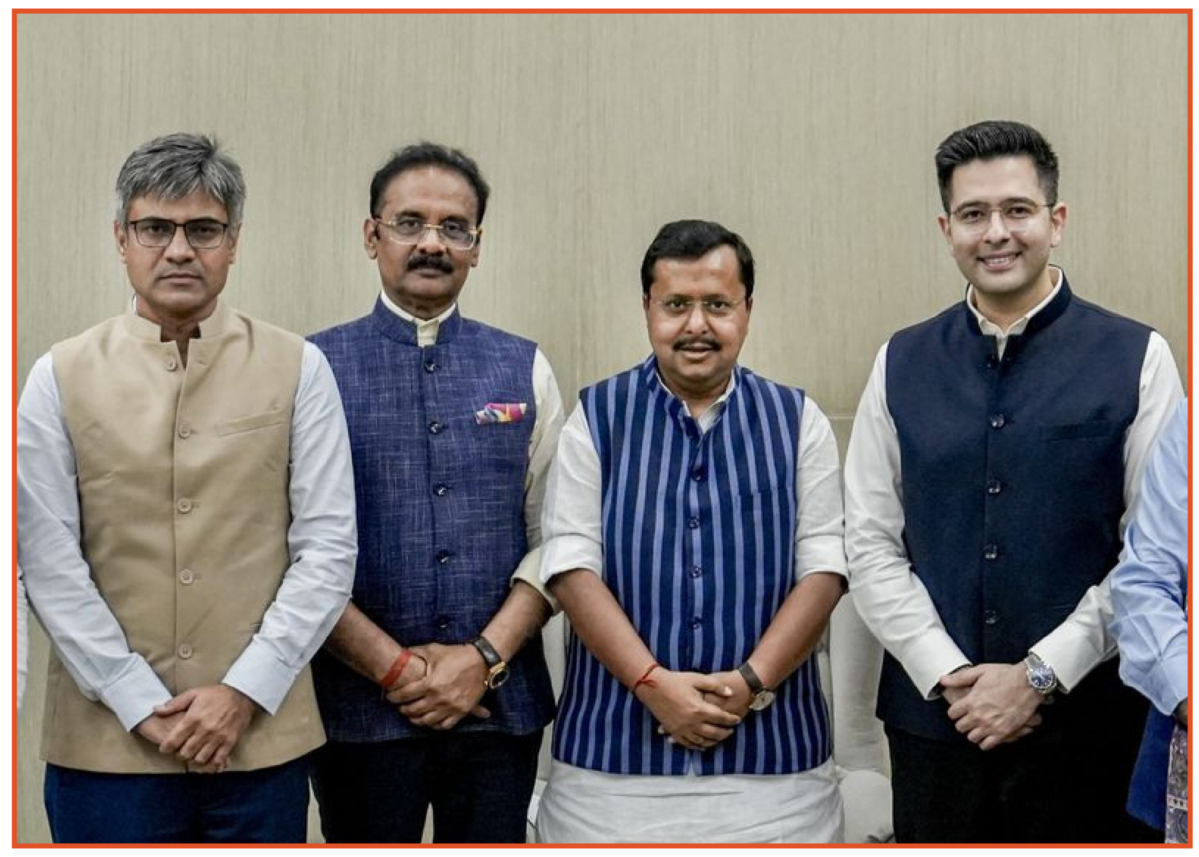

दूसरी तरफ़, भाजपा के नेता 'डबल इंजन सरकार' का नारा लगा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि अगर उन्हें देश के खाते से कुछ पाना है, तो राज्य में उसी पार्टी को चुना जाए, जिसकी केंद्र में सरकार हो। यानी भाजपा केंद्र से आर्थिक सहायता का लालच देकर पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में है। भाजपा वादा कर रही है कि अगर वह चुनाव जीतती है, तो राज्य में धर्म परिवर्तन के ख़िलाफ़ क़ानून बनाएगी। कुछ समय पहले भाजपा ने राज्य में कांग्रेस के फ्रंटलाइन नेताओं का पार्टी परिवर्तन कर के अपनी पार्टी में शामिल किया था, वहीं हाल ही में उसने आप के 6 राज्यसभा सदस्यों को तोड़कर भाजपा में शामिल करवा लिया। गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्यों के पार्टी परिवर्तन से कुछ दिन पहले ही उनमें से एक सदस्य के घर पर केंद्र सरकार की फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने छापा मारा था और अगले ही दिन उन की पार्टी परिवर्तन की घटना हो गई। दूसरी तरफ आप में पंजाब के 6 में से 2 पार्टी परिवर्तन वाले सदस्य गैर पंजाबी हैं। राजनीति में अनजान और कच्ची समझ रखने वाले, लेकिन उस समय आप ने राघव चड्ढा और संदीप पाठक को हीरो की तरह पेश करके, उन्हें पंजाब में बिना किसी संवैधानिक दायित्व के बहुत ज़्यादा पावर, राज्य के खर्च पर सिक्योरिटी देकर, और फिर उन्हें पंजाब से राज्यसभा मेंबरशिप के लिए नॉमिनेट करके अपनी पॉलिटिकल नादानी दिखाई है। अगर हम पंजाब के बारे केंद्र सरकार की पॉलिसी देखें, तो हमें वहां भी राजनीतिक गुरबत ही दिखाई देती है। भाजपा की केंद्र सरकार, लोगों की भलाई से ज़्यादा कॉर्पोरेट के फ़ायदे के लिए, पंजाब में खेती को इंडस्ट्रिलाइज़ेशन करने और इसमें लगी 35-40 फीसदी आबादी के एक बड़े हिस्से को खेती के पेशे से हटाने का इरादा रखती है, लेकिन इस आबादी के लिए एक विकल्प के तौर पर एक ठोस और सम्मानजनक काम के लिए कोई भरोसेमंद पॉलिसी लाने में कोई सीरियस नहीं दिखती। राज्य में बेरोजगारी और असमानता दूर करने हेतु संरचनात्मक समाधान पेश करने, जलवायु परिवर्तन प्रभावों और घटते भूजल स्तर को रोकने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती गुणवत्ता को सुधारने और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाजपा नेताओं द्वारा 'डबल इंजन सरकार' और 'धर्मांतरण विरोधी कानून' की पेशकश भी राज्य में राजनीतिक नासमझी को दर्शाती है। आप के राज्यसभा मेंबरों ने अपने दलबदल को यह कहकर सही ठहराया है कि पार्टी में उनका दम घुट रहा था। लेकिन सच तो यह है कि उनके पास न तो कोई लोगों का एजेंडा था, न सोच और न ही पक्का यकीन और न ही लोगों के हित में कुछ कहने का दम; अगर कुछ था, तो वह था पद और पावर की भूख। लालच और डर के कारण, दलबदल करने से उनका दम घुटना तो रुक गया, लेकिन लोगों के भरोसे का दम ज़रूर घुट गया। भाजपा उनके कंधों पर सवार होकर 2027 का चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है। ऐसी सोच पॉलिटिकल गरीबी का ही एक नमूना है। राजनीतिक गुरबत का एक और उदाहरण यह है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों की नाकामियों के भरोसे अपनी जीत पक्की मान रही है, और उसके सभी नेता मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जताते हुए एक-दूसरे से ही मुकाबले में हैं। ऐसे में, पंजाब के राजनेताओं का 'तूफान और दहाड़' और उनकी 'तू-तू, मैं-मैं' किसी भी सैद्धांतिक राजनीति से खाली है, जिसकी वजह से पंजाब राजनीतिक गरीबी की ओर बढ़ता दिख रहा है।

प्रेरणा

विपत्तियों के बीच खिलता व्यक्तित्व

दुनिया में हर व्यक्ति अपने जीवन को सुख, सफलता और उपलब्धियों से भरपूर देखना चाहता है। कोई भी जानबूझकर कठिनाइयों को नहीं चुनता, लेकिन जीवन का एक अटल सत्य यह है कि संघर्ष और चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में आती हैं। कुछ लोग इन परिस्थितियों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं चुनौतियों को अपनी शक्ति में बदल देते हैं। इतिहास में अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को अपने जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत बनाया। फ्रांसीसी दार्शनिक और साहित्यकार आल्बेयर कामू का जीवन इसी सत्य का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। आल्बेयर कामू का जन्म अल्जीरिया के एक अत्यंत साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। बचपन अभावों में बीता, लेकिन उनके भीतर जीवन के प्रति उत्साह और सपनों की कोई कमी नहीं थी। उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। खेल के मैदान में वे स्वयं को जीवंत महसूस करते थे और भविष्य में एक अध्यापक बनने का सपना देखते थे। उनके मन में भी वही आकांक्षाएँ थीं जो किसी भी युवा के मन में होती हैं। वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत थे और आशा से भरे हुए थे।

लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। एक समय ऐसा आया जब गंभीर बीमारी ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया और चिकित्सकों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यह रोग जीवन भर उनका पीछा कर सकता है। यह सुनना किसी भी युवा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता। एक ओर खेल का सपना टूट रहा था और दूसरी ओर स्वास्थ्य भी कमजोर पड़ रहा था। सामान्यतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा से भर जाता है और अपने भविष्य को अंधकारमय मानने लगता है।

जब उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि अब आगे क्या करोगे, तब उन्होंने जो उत्तर दिया, वह उनकी असाधारण सोच का परिचायक था। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि यदि जीवन सीमित है तो उसे और अधिक गहराई से जीना चाहिए। यह वाक्य केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण का सार था। उन्होंने परिस्थितियों के सामने हार मानने के बजाय उन्हें स्वीकार किया और जीवन के अर्थ को नए ढंग से समझने का प्रयास किया। मनुष्य के जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब वह कठिनाइयों को केवल समस्या के रूप में नहीं, बल्कि सीख के रूप में देखना शुरू करता है। अधिकांश लोग जीवन की बाधाओं को अपने सपनों के रास्ते की दीवार समझते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं दीवारों को सीढ़ियों में बदल देते हैं। कामू ने भी यही किया। बीमारी ने उनके शरीर को सीमित कर दिया, लेकिन उनके विचारों को और अधिक विस्तृत बना दिया। उन्होंने अपने अनुभवों, संघर्षों और जीवन के गहन प्रश्नों पर चिंतन करना शुरू किया। यही चिंतन आगे चलकर उनकी लेखनी की शक्ति बना।

समय बीतता गया और यूरोप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गया जिसे निराशा, युद्ध और असुरक्षा का समय कहा जा सकता है। चारों ओर हिंसा, भय और अनिश्चितता का वातावरण था। लोग भविष्य को लेकर चिंतित थे। मानवता जैसे अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न उठा रही थी। ऐसे समय में लोगों ने कामू से पूछा कि इतनी विपत्तियों के बीच आशा कहाँ है। उनका उत्तर अत्यंत गहरा था। उन्होंने कहा कि मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि संसार उसे क्या देता है, बल्कि इस बात में है कि वह विपत्ति के सामने किस प्रकार खड़ा रहता है।

यह विचार आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। आधुनिक जीवन में भी लोग अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। किसी को आर्थिक कठिनाइयाँ परेशान करती हैं, किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, तो किसी को पारिवारिक या सामाजिक संघर्ष। कई बार लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि परिस्थितियाँ उनके नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन वास्तव में मनुष्य का चरित्र इस बात से नहीं बनता कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से बनता है कि उसने उन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार किया।

जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। बहुत से लोग धन, पद और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भीतर से असंतुष्ट रहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग सीमित साधनों के बावजूद संतोष, आत्मविश्वास और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। इसका कारण यह है कि वास्तविक सफलता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति में छिपी होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और साहस का दीपक जला लेता है, तब बाहरी अंधकार उसका मार्ग नहीं रोक पाता। कामू के जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, लेकिन उससे प्राप्त अनुभव जीवन भर साथ रहते हैं। संघर्ष मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। वे उसे धैर्य, संवेदनशीलता और आत्मबोध प्रदान करते हैं। यदि जीवन में कभी कोई चुनौती न आए, तो व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान ही नहीं सकता। विपत्तियाँ ही हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का परिचय कराती हैं।

आज के समय में युवाओं के सामने प्रतिस्पर्धा, असफलता और अनिश्चितता जैसी अनेक चुनौतियाँ हैं। कई बार एक छोटी सी असफलता उन्हें हतोत्साहित कर देती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि महान उपलब्धियाँ अक्सर संघर्ष की भट्ठी में ही तैयार होती हैं। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठने का साहस रखता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। हार और असफलता जीवन का अंत नहीं होतीं, बल्कि वे हमें बेहतर बनने का अवसर देती हैं।

साहस का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य को कभी भय नहीं होता। साहस का वास्तविक अर्थ है भय और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहना। यही गुण मनुष्य को असाधारण बनाता है। जब व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। वह समझने लगता है कि हर चुनौती अपने भीतर कोई न कोई अवसर छिपाए होती है।

आल्बेयर कामू का जीवन हमें यही संदेश देता है कि जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, मनुष्य के पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता होती है। वह चाहे तो निराशा को अपना भाग्य बना सकता है और चाहे तो संघर्ष को अपनी शक्ति में बदल सकता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी आशा बनाए रखता है, वही जीवन की वास्तविक गहराई को समझ पाता है। विपत्तियाँ मनुष्य को रोकने के लिए नहीं आतीं, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने के लिए आती हैं। इसलिए जब भी जीवन में चुनौतियाँ आएँ, उनसे घबराने के बजाय उनका सामना साहस, धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए।

गृहिणियां राष्ट्र निर्माता हैं, समझिए कैसे? उनके कार्यगत योगदान को कदापि कम मत आंकिए

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने हाल ही में गृहिणियों के योगदान पर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि "गृहिणियां राष्ट्र निर्माता (Nation Builders) हैं" और उनके घरेलू व देखभाल संबंधी कार्यों का वास्तविक आर्थिक मूल्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रमुख टिप्पणियों में कहा कि गृहिणी को केवल "आश्रित" (dependent) मानना गलत है; वास्तव में पूरा परिवार उनके श्रम और देखभाल पर निर्भर रहता है। लिहाजा, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य भारत की GDP में अनुमानतः 15-17% तक योगदान देता है, फिर भी उसे पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती। वह गृहिणयां ही हैं जो बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा, संस्कार और मानव संसाधन निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती हैं। इसलिए अदालत ने कहा कि घरेलू कार्य को आर्थिक विश्लेषण से बाहर रखना उचित नहीं है और कानून को गृहिणियों के श्रम, सेवा और त्याग का मूल्य स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष यह कि गृहिणियां राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए उनके कार्यगत योगदान को कम मत आंकिए।

देखा जाए तो एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में गृहिणी के घरेलू योगदान का मूल्यांकन करते हुए कम-से-कम 30,000 प्रतिमाह का मानक निर्धारित किया है तथा "loss of domestic care" को अलग क्षतिपूर्ति मद के रूप में मान्यता दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि, "गृहिणी का घर में किया गया कार्य उसके कार्यालय जाने वाले पति के काम से कम मूल्यवान नहीं है।"

इसलिए न्यायपालिका का दृष्टिकोण अब स्पष्ट रूप से यह है कि गृहिणियां केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि आर्थिक योगदानकर्ता और राष्ट्र निर्माता हैं। चुनौती अब यह है कि सरकारें, निजी संस्थान और समाज इस न्यायिक मान्यता को सामाजिक और आर्थिक नीतियों में कितना उतारते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि गृहिणियों का योगदान भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि उनके श्रम को अक्सर "काम" के बजाय "कर्तव्य" मान लिया जाता है।

इसी कारण उनके योगदान को वह संस्थागत मान्यता नहीं मिल पाती जिसकी वे हकदार हैं। सवाल है कि गृहिणियों का आर्थिक योगदान कितना बड़ा है? तो अर्थशास्त्रियों और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार यदि घर के भीतर किए जाने वाले कार्य—जैसे भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, घरेलू प्रबंधन, भावनात्मक देखभाल आदि—का बाजार मूल्य जोड़ा जाए, तो इसका योगदान GDP के 15% से 40% तक आंका गया है। भारत में कई अध्ययनों ने इसे लगभग 15-17% या उससे भी अधिक बताया है।

पहला, जीडीपी की गणना का तरीकाः GDP केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को गिनता है जिनका बाजार में लेन-देन होता है। गृहिणी का श्रम घर के भीतर होता है, इसलिए वह राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में सीधे नहीं दिखता।

दूसरा, ऐतिहासिक सामाजिक दृष्टिकोणः सदियों से घरेलू कार्यों को महिलाओं का "स्वाभाविक दायित्व" माना गया। जब किसी कार्य को कर्तव्य मान लिया जाता है, तो उसका आर्थिक मूल्यांकन कम हो जाता है।

तीसरा, श्रम का अदृश्य होनाः एक गृहिणी दिनभर में दर्जनों काम करती है, लेकिन वे छोटे-छोटे हिस्सों में बंटे होते हैं। इसलिए उनका श्रम उतना दिखाई नहीं देता जितना किसी कार्यालय या फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति का।

चौथा, नीति निर्माण में कम प्रतिनिधित्वः सत्ता और नीति-निर्माण संस्थानों में लंबे समय तक पुरुषों का वर्चस्व रहा। परिणामस्वरूप घरेलू श्रम के आर्थिक मूल्यांकन का प्रश्न प्राथमिकता नहीं बन पाया।

पांचवां, वेतन और मूल्य का भ्रमः समाज अक्सर मानता है कि जिस काम के बदले वेतन नहीं मिलता, उसका आर्थिक मूल्य भी नहीं है। जबकि गृहिणी का श्रम परिवार की आय और उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है।

पहला, घरेलू श्रम का नियमित आर्थिक मूल्यांकन। दूसरा, जनगणना और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में गृहिणी श्रम का अलग लेखा-जोखा। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा योजनाओं का विस्तार। चौथा, घरेलू कार्यों को "अनपेड वर्क" के रूप में नीति दस्तावेजों में मान्यता। और पांचवां, परिवारों में घरेलू जिम्मेदारियों का अधिक समान वितरण।

गृहिणी केवल घर नहीं संभालती, वह भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करती है। एक शिक्षक, डॉक्टर, सैनिक, वैज्ञानिक, उद्यमी या नेता बनने से पहले हर व्यक्ति किसी परिवार में पलता-बढ़ता है। उस प्रक्रिया में गृहिणियों का योगदान आधारशिला जैसा होता है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गृहिणियां केवल परिवार निर्माता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता भी हैं। चुनौती यह है कि समाज और संस्थाएं इस योगदान को भावनात्मक सम्मान के साथ-साथ आर्थिक और नीतिगत मान्यता भी दें।

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो" — नामक कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पंक्ति भारतीय समाज में स्त्री के सम्मान का आदर्श प्रस्तुत करती है। लेकिन आज यह प्रश्न स्वाभाविक है कि केवल श्रद्धा, सम्मान और प्रशंसा के शब्दों से कब तक काम चलेगा? यदि एक ओर स्त्री को "देवी", "शक्ति", "मां" और "राष्ट्र निर्माता" कहा जाए, और दूसरी ओर उसके श्रम, अधिकारों और योगदान को उचित मान्यता न मिले, तो यह विरोधाभास ही माना जाएगा।

अभियान

रहस्य, आध्यात्म और ऊर्जा का संगम: कसार देवी की अद्भुत दुनिया

भारत को सदियों से आध्यात्म, योग, ध्यान और रहस्यमयी स्थलों की भूमि कहा जाता रहा है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि यहां प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो दुनिया के अन्य स्थानों पर दुर्लभ है। उत्तराखंड के पहाड़ों में अनेक प्राचीन मंदिर और तपस्थल मौजूद हैं, जिनसे जुड़ी कथाएं लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। इन्हीं रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थलों में एक नाम है अल्मोड़ा के निकट स्थित कसार देवी मंदिर का। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक शांति और रहस्यमयी प्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। यही कारण है कि वर्षों से यह स्थान श्रद्धालुओं, योग साधकों, शोधकर्ताओं और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है।

कुमाऊं क्षेत्र की सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित कसार देवी मंदिर समुद्र तल से लगभग 2,100 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यहां पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज मन को प्रभावित करती है, वह है आसपास फैली प्राकृतिक सुंदरता। चारों ओर देवदार और चीड़ के घने जंगल, दूर-दूर तक फैली हिमालय की चोटियां, स्वच्छ हवा और अद्भुत शांति इस स्थान को एक अलग ही पहचान प्रदान करती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं यहां ध्यानमग्न होकर बैठी हो। यही कारण है कि यहां आने वाले अधिकांश लोग इस स्थान को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव का केंद्र मानते हैं।

कसार देवी मंदिर का इतिहास भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर दूसरी शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहां देवी शक्ति का निवास है और सदियों से लोग इस स्थान को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते आए हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों की आस्था इस मंदिर से गहराई से जुड़ी हुई है। उनका विश्वास है कि यहां मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य फलित होती है।

हालांकि कसार देवी मंदिर को केवल धार्मिक महत्व के कारण ही प्रसिद्धि नहीं मिली। इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण वह रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और आध्यात्मिक साधकों को समान रूप से आकर्षित किया है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र विशेष प्रकार की भू-चुंबकीय ऊर्जा से प्रभावित है। कई लोगों का दावा है कि यहां पहुंचते ही उन्हें मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और गहन एकाग्रता का अनुभव होता है। ध्यान करने वाले साधक बताते हैं कि इस स्थान पर ध्यान लगाना अन्य स्थानों की तुलना में अधिक सहज महसूस होता है। यही अनुभव वर्षों से लोगों को इस रहस्य को समझने के लिए प्रेरित करता रहा है। कसार देवी मंदिर को लेकर अक्सर यह दावा किया जाता है कि यह क्षेत्र पृथ्वी की उन विशेष जगहों में से एक है जहां भू-चुंबकीय गतिविधियां असामान्य रूप से सक्रिय हैं। इसी संदर्भ में वैन एलेन बेल्ट का उल्लेख किया जाता है। वैन एलेन बेल्ट वास्तव में पृथ्वी के चारों ओर मौजूद विकिरण क्षेत्रों को कहा जाता है, जिनका अध्ययन अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाता है। लोकप्रिय मान्यताओं में यह कहा जाता है कि कसार देवी क्षेत्र में कुछ ऐसी भू-चुंबकीय विशेषताएं पाई गई हैं जो इसे दुनिया के कुछ चुनिंदा ऊर्जा केंद्रों के समान बनाती हैं। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिक समुदाय में अलग-अलग मत हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि इस स्थान की प्राकृतिक और भौगोलिक विशेषताओं ने इसे विशिष्ट पहचान अवश्य प्रदान की है।

इस मंदिर की प्रसिद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण स्वामी विवेकानंद भी हैं। वर्ष 1890 के आसपास स्वामी विवेकानंद कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहां एक गुफा में ध्यान और साधना की थी। इस स्थान की शांति और आध्यात्मिक वातावरण ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया था। बाद में उन्होंने अपने अनुभवों का उल्लेख भी किया। स्वामी विवेकानंद जैसे महान चिंतक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का इस स्थान से जुड़ना इसकी प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाता है। आज भी अनेक लोग उसी आध्यात्मिक अनुभूति की तलाश में यहां पहुंचते हैं जिसे कभी विवेकानंद ने अनुभव किया था।

समय के साथ कसार देवी मंदिर केवल भारतीय श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहा। बीसवीं शताब्दी के मध्य में यह स्थान विदेशी यात्रियों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के बीच भी लोकप्रिय हो गया। विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशक में यहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचे। उस समय विश्वभर में हिप्पी आंदोलन का प्रभाव था और लोग आध्यात्मिक शांति तथा जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में भारत आ रहे थे। कसार देवी का शांत वातावरण और रहस्यमयी आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच लाया। धीरे-धीरे यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया और इसे "हिप्पी हिल" के नाम से भी जाना जाने लगा।

विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जॉर्ज हैरिसन, प्रसिद्ध गायक बॉब डायलन, कवि एलन गिन्सबर्ग और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय हस्तियां यहां आ चुकी हैं। इन लोगों ने इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की। उनके आगमन ने कसार देवी को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी अनेक विदेशी पर्यटक यहां ध्यान, योग और आत्मिक शांति की तलाश में आते हैं।

कसार देवी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव को अलग-अलग शब्दों में व्यक्त करता है। कोई इसे मानसिक शांति का केंद्र कहता है, कोई ऊर्जा का स्रोत मानता है और कोई इसे प्रकृति तथा अध्यात्म के अद्भुत संगम के रूप में देखता है। यहां की नीरवता मन को भीतर तक स्पर्श करती है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और मानसिक दबाव से दूर यह स्थान लोगों को स्वयं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। शायद यही कारण है कि यहां पहुंचने वाले अनेक लोग कुछ समय तक मौन रहना पसंद करते हैं और प्रकृति के बीच बैठकर आत्मचिंतन करते हैं।

मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। निकट स्थित बिनसर वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां विभिन्न प्रकार के पक्षी, वन्यजीव और दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं और पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंजता है, तब यहां का दृश्य अविस्मरणीय बन जाता है।

स्थानीय लोगों के जीवन में भी कसार देवी मंदिर का विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां विशाल मेला आयोजित होता है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और देवी की पूजा-अर्चना करते हैं। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। मेले के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से भर जाता है और दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं।

वर्तमान समय में जब विज्ञान और तकनीक ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर ली है, तब भी कुछ स्थान ऐसे हैं जो लोगों के मन में जिज्ञासा और आश्चर्य पैदा करते हैं। कसार देवी मंदिर भी उन्हीं स्थानों में से एक है। यहां आकर लोग केवल किसी रहस्य को समझने का प्रयास नहीं करते, बल्कि स्वयं को समझने की कोशिश भी करते हैं। शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मनुष्य को बाहरी दुनिया से हटाकर उसके भीतर की यात्रा पर ले जाता है।

कसार देवी मंदिर इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति, अध्यात्म और मानवीय जिज्ञासा का संबंध कितना गहरा हो सकता है। चाहे कोई इसे धार्मिक आस्था के रूप में देखे, भू-चुंबकीय रहस्य के रूप में समझे या फिर मानसिक शांति के केंद्र के रूप में अनुभव करे, यह स्थान हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नया अवश्य देता है। हिमालय की गोद में स्थित यह मंदिर आज भी लाखों लोगों के लिए श्रद्धा, रहस्य और प्रेरणा का अद्भुत प्रतीक बना हुआ है। यहां आने वाला व्यक्ति केवल एक मंदिर के दर्शन करके नहीं लौटता, बल्कि अपने साथ एक ऐसा अनुभव लेकर जाता है जो लंबे समय तक उसकी स्मृतियों में जीवित रहता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

बारह वर्ष जनविश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

गुजरात के गांवों में विकास की गति तेज

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 6 लाख से अधिक परिवारों को मिले घर
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 4,557 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन
- गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन लिमिटेड के प्रयासों से 26 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का हुआ आर्थिक सशक्तीकरण
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वॉटरशेड कंपोनेंट) के तहत 617 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1.36 लाख से अधिक कार्य पूर्ण
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 44 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण

गांधीनगर : गुजरात ने पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों के नेतृत्व में गुजरात के गांवों का कायाकल्प हो रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दूरदर्शी मार्गदर्शन और ग्रामीण विकास मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया के नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग ने प्रगति के नए शिखर हासिल किए हैं। राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पीएम - जनमन, वॉटरशेड डेवलपमेंट तथा गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन लिमिटेड (जीएलपीसी) की अनेक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की जा रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा के लिए आशीर्वाद के रुप में साबित हुई है। इस योजना के माध्यम से पिछले 12 वर्षों में राज्य में कुल 4,557 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। योजनांतर्गत जल संरक्षण, कृषि भूमि विकास, वृक्षारोपण तथा पशुपालन आधारित 19 लाख से अधिक श्रम केंद्रित कार्य किए गए हैं।

केंद्र और राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस विजन के तहत मनरेगा में पारदर्शिता लाने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) लागू किए गए हैं। इसके अलावा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप, ड्रोन निरीक्षण, जियोटैगिंग और जियोफेंसिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा कार्यों की पुनरावृत्ति भी रुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) : बेघर परिवारों को मिला आश्रय

ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को गौरवपूर्ण जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 से लागू प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक 8.29 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 30 अप्रैल 2026 तक 6.99 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 1.38 लाख से अधिक आवास निर्माणाधीन हैं। इस कार्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 9,213 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया गया है।

केंद्र तथा राज्य सरकार के 60:40 के भागीदारी वाली इस योजना में लाभार्थी को नियमित रूप से 1.20 लाख रुपए की सहायता मिलती है। लेकिन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के संवेदनशील दृष्टिकोण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 100 प्रतिशत राज्य अंश के तहत रूफ-कास्ट स्तर पर अतिरिक्त 50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है, जिससे कुल सहायता राशि 1.70 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत 90 दिनों की मजदूरी के रूप में 25,920 रुपए तथा शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपए की सहायता भी प्रदान की जाती है। समय पर आवास पूरा करने वाले लाभार्थियों को 'मुख्यमंत्री प्रोत्साहक योजना' के तहत अतिरिक्त 20 हजार रुपए तथा महिलाओं के लिए बाथरूम निर्माण के लिए 5 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।

पीएम - जनमन : आदिम जनजातीय समूहों के बेघर परिवारों को मिला आश्रय

वर्ष 2023 से शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम - जनमन) के अंतर्गत राज्य के अत्यंत पिछड़े आदिम जनजातीय समूहों (पीवीटीजीस) जैसे काथोडी, कोटवाळिया, पाढर, सिद्दी और कोलगा परिवारों के लिए 226 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 9,151 पक्के आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। इस योजना में लाभार्थी को 2 लाख रुपए की सहायता सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : ओडीएफ प्लस मॉडल की ओर अग्रसर गुजरात

ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में गुजरात ने देशभर में अग्रणी स्थान बनाए रखा है। पिछले 12 वर्षों में इस मिशन के अंतर्गत 7,162.37 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले 5,994.54 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्र को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए जाने के बाद अब फेज-2 के तहत 'ओडीएफ प्लस मॉडल' गांवों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 44.82 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर ठोस और तरल कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए 1.74 लाख सामुदायिक सोकपिट, 56,369 सामुदायिक कम्पोस्ट पिट तथा 13,575 सेग्रीगेशन शेड बनाए गए हैं। 'वेस्ट टू वेल्थ' दृष्टिकोण के तहत गोबरधन योजना के अंतर्गत 33 जिलों में 38 क्लस्टर आधारित बायोगैस प्लांट और 14,000 व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वॉटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट) के तहत पिछले 12 वर्षों में 617.90 करोड़ रुपए की लागत से 1,36,589 कार्य पूरे किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में भूमि, जल, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन कर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, भूमि सुधार तथा आजीविका विकास जैसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं; जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। योजना अंतर्गत चैकडेम, तालाब, कॉजवे तथा खेत तालाब जैसे जल संचयन ढांचे बनाए जाते हैं, जिससे वर्षा का पानी बहकर न जाए और उसका संग्रहण हो सके। पानी के जमीन में रिसाव से भूजल स्तर में वृद्धि होती है तथा कुओं और बोरवेलों में पानी की उपलब्धता बढ़ती है।

जीएलपीसी : सखी मंडलों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण और 'लखपति दीदी' का संकल्प

गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड (जीएलपीसी) राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रभावी माध्यम बनी है। डे-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य के 248 तहसीलों में 26.25 लाख ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर 2.82 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीस) का गठन किया गया है। इन समूहों को रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड तथा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक लिंकेज उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 'लखपति दीदी' अभियान के अंतर्गत गुजरात की 6 लाख से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं। सखी मंडलों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय मेले, सरस मेले तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही 300 से अधिक केंद्रों पर संचालित 'मंगलम कैंटीन' महिलाओं को नियमित आय का स्रोत प्रदान कर रही हैं।

भावनगर एवं राजकोट मंडल के माननीय सांसदो के साथ बैठक में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने भावनगर एवं राजकोट मंडल के अन्तर्गत आनेवाले संसदीय क्षेत्रों के माननीय सांसदो के साथ राजकोट में बैठक की। सर्वप्रथम महाप्रबंधक श्री पाण्डेय द्वारा उपस्थित सांसदो का स्वागत किया गया तथा उन्हे भावनगर व राजकोट मंडल में नवीनतम यात्री सुविधाओं व उपलब्धियों की जानकारी दी गई। बैठक के दौरान माननीय सांसदो द्वारा उनके क्षेत्र की रेल समस्याओं, परियोजनाओं, ट्रेनों के स्टापेज, नयी ट्रेन चलाने तथा ट्रेनों के विस्तार, ट्रेनों के फेरे बढाने और ढांचागत परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं बहुमूल्य सुझाव दिये गए।

भावनगर एवं राजकोट मंडल क्षेत्राधिकार के कुल 6 माननीय सांसदों ने इस बैठक में भाग लिया, जिनमें माननीय श्री परषोत्तमभाई रुपाला, श्रीमती पूनमबेन माडम, श्री रामभाई मोकरिया, श्री केसरीदेवसिंह झाला तथा श्री राजेशभाई चुड़ासमा, श्री भरतभाई सुतरिया शामिल रहे। पोरबंदर के माननीय सांसद तथा केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा मामले एवं खेल मंत्री, श्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया के प्रतिनिधि तथा माननीय सांसद श्री चंदूभाई शिहोरा के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में भावनगर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, राजकोट मंडल रेल प्रबंधक श्री गिरिराज कुमार मीना तथा पश्चिम रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक (सामान्य) श्री उज्जवल देव ने किया।

बैठक के दौरान, महाप्रबंधक श्री पाण्डेय ने माननीय सांसदों को वर्तमान में चल रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया और कहा कि पश्चिम रेलवे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न यात्री सुविधाओं को प्रदान करने में हमेशा अग्रणी रही है। माननीय सांसदों ने भी अपनी मांगों को रखा और इन मंडलों में चल रही परियोजनाओं की सकारात्मक प्रगति के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से करजण में हिताची एनर्जी द्वारा लगभग 2,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित होने वाली फैक्ट्री का शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- इस प्रोजेक्ट से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और एमएसएमई क्षेत्र को वेग मिलेगा
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' के संकल्प को साकार करने में गुजरात अग्रसर
- हिताची और गुजरात का 60 वर्ष पुराना अटूट संबंध और अधिक सुदृढ हुआहिताची
- एनर्जी इंडिया के सीईओ श्री वेणु ने गुजरात के प्रगतिशील इकोसिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में राज्य की अग्रणी भूमिका की सराहना की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा जिले के करजण में हिताची एनर्जी द्वारा लगभग 2,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश से स्थापित की जाने वाली नई पावर ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबे और सफल कार्यकाल के लिए श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी लीडरशिप में भारत आज विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है।

मुख्यमंत्री ने करजण स्थित नए लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर प्लांट की स्थापना के लिए कंपनी को बधाई देते हुए कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' अभियान को और सुदृढ बनाएगी तथा देश के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस नए प्लांट द्वारा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, इस परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्र की एमएसएमई इकाइयों के लिए भी विकास के नए द्वार खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई 'वाइब्रंट गुजरात समिट' के परिणामस्वरुप आज गुजरात विश्वभर के उद्योगपतियों के लिए निवेश का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। हिताची तथा गुजरात के बीच 60 वर्ष पुराना संबंध का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियों का गुजरात पर विश्वास लगातार बढ़ता गया है। गुजरात के मजबूत औद्योगिक वातावरण, पारदर्शी नीतियों और उत्कृष्ट कानून-व्यवस्था के कारण आज फॉर्च्यून-500 में शामिल विश्व की बड़ी कंपनियों के लिए गुजरात 'सेकंड होम' बन गया है। राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात को 'इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट' के रूप में स्थापित किया है। कच्छ के खावडा में विकसित हो रहा 37 गीगावॉट का रिन्यूएबल हाइब्रिड पार्क पूर्ण होने के बाद गुजरात देश की 'एनर्जी कैपिटल' बन जाएगा। ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नीतियों के द्वारा राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास साध रहा है।

आगामी दिनों में बढ़ रही ग्रीन एनर्जी की मांग को पूरा करने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन सिस्टम आवश्यक है; जिसमें हिताची एनर्जी की यह नई सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'विकसित भारत @ 2047' के संकल्प को साकार करने में आत्मनिर्भर ऊर्जा अर्थव्यवस्था द्वारा गुजरात महत्वपूर्ण योगदान देगा।

हिताची एनर्जी इन्डिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ श्री वेणु ने भारत की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि, "यह नई फैसिलिटी एक 'डिजिटल-फर्स्ट' ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री होगी, जो हाई - एंड मैन्युफेक्चरिंग द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के एकीकरण को वेग देगा तथा भारत को ट्रांसफॉर्मर्स के वैश्विक लॉन्चपैड के रूप में स्थापित करेगी।"

श्री वेणु ने गुजरात के प्रगतिशील इकोसिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में राज्य की अग्रणी भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह परियोजना 'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत उच्च कौशल आधारित रोजगार का सृजन करेगी तथा स्थानीय सप्लाई चेन को मजबूत बनाएगी। उन्होंने जोड़ा कि कहा कि कंपनी अगले 25 वर्षों तक भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के प्रति कटिबद्ध है तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना भी जारी रखेगी।

हिताची एनर्जी के ट्रांसफॉर्मर बिजनेस के ग्लोबल सीईओ श्री ब्रूनो मेलिस ने भारत के ऊर्जा भविष्य और अगले 25 वर्षों के सतत विकास को वेग देने के लिए कंपनी की मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में 75 वर्षों से अधिक की समृद्ध विरासत के साथ कंपनी वर्ष 2028 तक एक नई अत्याधुनिक फैक्ट्री शुरू करने का लक्ष्य रखती है। यह फैक्ट्री 'मेक इन इंडिया' अभियान को और मजबूत बनाएगी तथा टेक्नोलॉजी के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने बल देते हुए कहा कि यह नई सुविधा केवल एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं होगा, बल्कि इंजीनियरिंग, इनोवेशन और प्रतिभाशाली लोगों के सहयोग से विकसित अत्याधुनिक सिस्टम होगी, जो भारत और विश्व की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री के करकमलों से जमनाबाई जनरल अस्पताल के प्रतिनिधि को कंपनी के सीएसआर फंड से भेंट की गई एम्बुलेंस की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई।

इस कार्यक्रम में वडोदरा के सांसद श्री हेंमागभाई जोशी, करजण के विधायक श्री अक्षयभाई पटेल, राज्य के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में राज्य की ऐतिहासिक पहल : गुजरात नॉलेज सोसाइटी (जीकेएस) तथा अमेरिका की वैश्विक अग्रणी कंपनी बेंटले सिस्टम्स के बीच रणनीतिक भागीदारी

- एमओयू से राज्य के सभी 16 सरकारी इंजीनियरिंग तथा 31 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 14800 से अधिक विद्यार्थियों और 300 से अधिक अध्यापकों को मिलेगा आधुनिक टेक्नोलॉजी का निःशुल्क ज्ञान
- सरकार पर किसी भी प्रकार के वित्तीय बोझ के बिना विद्यार्थियों को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, वॉटर नेटवर्क तथा डिजिटल ट्विन जैसे क्षेत्रों में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिलेगा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गुजरात नॉलेज सोसाइटी (जीकेएस) और अमेरिका की वैश्विक अग्रणी कंपनी बेंटले सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच रणनीतिक भागीदारी का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा निदेशक कार्यालय अंतर्गत कार्यरत गुजरात नॉलेज सोसाइटी (जीकेएस) तथा अमेरिका की डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की वैश्विक अग्रणी कंपनी बेंटले सिस्टम्स के बीच एक महत्वपूर्ण अवाणिज्यक (नॉन-कॉमर्शियल) रणनीतिक भागीदारी के लिए एमओयू किया गया है। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य राज्य के इंजीनियरिंग क्षेत्र के विद्यार्थियों को ग्लोबल इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज से सज्ज कर रोजगारपरक बनाना है।

इस भागीदारी अंतर्गत राज्य के सभी 16 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा 31 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के लगभग 300 से अधिक अध्यापकों के लिए बेंटले के वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा विशेष फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) का आयोजन किया जाएगा। इस अनूठी पहल का सीधा लाभ सिविल इंजीनियरिंग तथा उससे सम्बद्ध शाखाओं के लगभग 14800 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को माइक्रोस्टेशन, ओपनरोड्स, ओपनफ्लोस, सिंक्रो तथा डिजिटल ट्विन जैसे अत्याधुनिक डिजिटल इंजीनियरिंग टूल्स पर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा; प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, हेकाथॉन तथा डिजाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में व्यावहारिक एवं तकनीकी कौशल का सुदृढ़ विकास किया जाएगा।

इस प्रस्तावित एमओयू अंतर्गत राज्य की तकनीकी शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को 65 से अधिक 'इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड' बेंटले सॉफ्टवेयर निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त; विद्यार्थी घर बैठे या कॉलेज में अपनी अनुकूलता से सीख सकें; इसके लिए उन्हें 'बेंटले लर्न प्लेटफॉर्म' के माध्यम से सेल्फ-लर्निंग व अत्याधुनिक डिजिटल एजुकेशन की विशेष सुविधा दी जाएगी। इस पहल से विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहते हुए वास्तविक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रक्रिया और लाइव केस स्टडीज द्वारा सीधा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को गुजरात नॉलेज सोसाइटी तथा बेंटले सिस्टम्स द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जो विद्यार्थियों के लिए वैश्विक स्तर के डिजिटल बेस तथा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर समान बनेगा। इसी प्रकार; विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उद्योग जगत के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ सीधा संवाद, स्पेशल गेस्ट लैक्चर्स, इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल विजिट्स का भी व्यापक आयोजन किया जाएगा।

यह पहल केन्द्र सरकार के 'स्किल इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020' के विजन के साथ सुसंगत है। इस शैक्षणिक जुड़ाव के अंतर्गत राज्य के भावी इंजीनियर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, स्मार्ट वॉटर नेटवर्क तथा डिजिटल ट्विन जैसी आगामी पीढ़ी की आधुनिक टेक्नोलॉजी में पूर्णतः निपुण एवं सक्षम बनेंगे।

इस भागीदारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राज्य सरकार पर किसी भी प्रकारके आर्थिक व वित्तीय बोझ के बिना तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सकेगा। इस ग्लोबल कनेक्ट से गुजरात के विद्यार्थी अधिक कुशल, उद्योग-सज्ज (इंडस्ट्री-रेडी) तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगे, जिसके दीर्घकालीन परिणाम के रूप में राज्य के बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वय में गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और गुजरात कुशल मानवबल (स्किल्ड मैनपावर) हब बनेगा। इस प्रकार; आज के डिजिटल युग में राज्य के युवा इंजीनियरों को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए गुजरात सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है।

अहमदाबाद के समग्र विकास एवं रेलवे अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं रेलवे अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक

स्टेशन पुनर्विकास, 'फाटक मुक्त गुजरात' तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार पर हुई व्यापक चर्चा

अहमदाबाद के समग्र विकास, रेलवे अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जून, 2026 को अहमदाबाद के माननीय महापौर श्री हितेश बारोट, अहमदाबाद पश्चिम के माननीय सांसद श्री दिनेश मकवाना, अहमदाबाद महानगरपालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री कमलेश पटेल तथा दरियापुर के माननीय विधायक श्री कौशिक जैन ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में रेलवे एवं अहमदाबाद महानगरपालिका के मध्य बेहतर समन्वय के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक एवं जनहितकारी विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के दौरान रेलवे अवसंरचना के समग्र सुदृढ़ीकरण, स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं, लेवल क्रॉसिंग उन्मूलन तथा 'फाटक मुक्त भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) एवं रोड अंडर ब्रिज (RUB) के निर्माण, नई रेल लाइनों के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन एवं सार्थक चर्चा की गई। क्षेत्र के तीव्र शहरी विकास एवं बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक, सुरक्षित एवं निर्बाध रेल संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बहु-एजेंसी समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में माननीय महापौर श्री हितेश बारोट ने आंबली रोड स्टेशन के आसपास स्थित रेलवे भूमि के समुचित विकास एवं उसके बेहतर उपयोग के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए तथा शहर के तीव्र विकास को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन योजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। अहमदाबाद महानगरपालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री कमलेश पटेल ने मणिनगर स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग संख्या-308 पर प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज के संबंध में स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाओं एवं सुझावों से अवगत कराते हुए रेलवे एवं अहमदाबाद महानगरपालिका के समन्वित प्रयासों से इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया। दरियापुर के माननीय विधायक श्री कौशिक जैन ने अहमदाबाद स्टेशन के आसपास उपलब्ध रेलवे भूमि के ऐसे विकास का सुझाव दिया, जिससे स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारिक गतिविधियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

अहमदाबाद पश्चिम के माननीय सांसद श्री दिनेश मकवाना ने अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अधोसंरचनात्मक एवं जनसुविधा विषयों को बैठक में रखते हुए रेलवे परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ओम नगर फाटक पर रोड अंडर ब्रिज के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कहा और शीघ्र पूरा करने के लिए कहा। मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने बैठक के दौरान असारवा स्टेशन के चमनपुरा साइड पर द्वितीय प्रवेश द्वार की स्थापना, चामुंडा ब्रिज से बेहतर संपर्क व्यवस्था विकसित करने तथा प्लेटफॉर्म के विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में भविष्य में आवश्यक अधोसंरचनात्मक विकास के माध्यम से इसे देश के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

बैठक के दौरान मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने जानकारी दी कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा 100 लाइनों वाला कोचिंग डिपो वटवा में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गोरा-घूमा रोड अंडर ब्रिज (RUB) को शीघ्र ही आम जनता को समर्पित किए जाने के संबंध में भी सकारात्मक चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्ष : गुजरात एक मजबूत और सर्वसमावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ देशभर में अव्वल

▸▸ गुजरात में आज 19,000 से अधिक डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत, लगातार पांच वर्षों से केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में 'बेस्ट परफॉर्मर स्टेट'

▸▸ स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत 13,047 से अधिक स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स को पीओसी के स्तर पर सहायता, 4000 से अधिक आईपीआर फाइल किए गए

▸▸ 'आई-हब' द्वारा लगभग 750 स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन और वित्तीय सहायता, इन स्टार्टअप्स द्वारा 4000 से अधिक रोजगार का सृजन

▸▸ महिला उद्यमियों के लिए 'वीस्टार्ट' पहल के अंतर्गत 269 महिला-संचालित स्टार्टअप्स को सहायता

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि यदि युवाओं के आइडियाज को उचित प्लेटफॉर्म, नीतिगत सहयोग और संसाधन मिलें, तो वे राष्ट्रनिर्माण के सबसे बड़े भागीदार बन सकते हैं। इसी सोच के साथ, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'स्टार्टअप इंडिया' पहल शुरू की गई, जिससे लाखों युवाओं को 'जॉब सीकर' से 'जॉब क्रिएटर' बनने की प्रेरणा मिली है।

उल्लेखनीय है कि 26 मई, 2026 को श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कर्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 12 वर्षों के दौरान देश में उद्यमशीलता की एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ है, और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम मबजूत हुआ है। उनके नेतृत्व में गत 12 वर्षों के दौरान गुजरात ने भी स्टार्टअप और इनोवेशन यानी नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात औद्योगिक विकास का केंद्र होने के साथ ही देश के एक अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है।

भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त 19,000 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ गुजरात आज देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। डीपीआईआईटी की स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात लगातार पांच वर्षों से 'बेस्ट परफॉर्मर स्टेट' बना हुआ है, जो दिखाता है कि सहायक नीतियों और नियोजित पहलों के जरिए राज्य में एक मजबूत और सर्वसमावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया गया है।

स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत 13,047 से अधिक स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के स्तर पर सहायता

राज्य के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा स्टार्टअप और इनोवेशन के माध्यम से युवाओं की सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने 2017-18 से पांच वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी (एसएसआईपी) घोषित की थी। इस पॉलिसी को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में वर्ष 2022 में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 (एसएसआईपी 2.0) लॉन्च की गई। इस पॉलिसी के अंतर्गत नए क्षेत्रों के साथ-साथ परंपरागत और नए युग की टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि एसएसआईपी 1.0 और 2.0 के तहत अब तक कुल 13,047 से अधिक स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) के स्तर पर सहायता दी गई है, जबकि 4043 से अधिक बौद्धिक संपदा अधिकार (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट-आईपीआर) फाइल किए गए हैं। एसएसआईपी के तहत कुल 3287 से अधिक स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और इनक्यूबेशन सहायता दी गई है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन को आर्थिक सहायता देने के लिए एसएसआईपी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं द्वारा 36.43 करोड़ रुपए के एसएसआईपी फंड का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, एसएसआईपी 1.0 और 2.0 के अंतर्गत पॉलिसी लागू होने के बाद से अब तक जागरूकता अभियान के माध्यम से 22.72 लाख से अधिक छात्रों को स्टार्टअप्स के विषय में मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया है।

इतना ही नहीं, एसएसआईपी 2.0 पोर्टल पर अब तक स्कूली छात्रों के 1948 से अधिक स्टार्टअप प्रस्ताव रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से लगभग 1141 छात्रों के स्टार्टअप प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। एसएसआईपी आज स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों को मार्गदर्शन, मेंटरशिप, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच जैसी सर्वग्राही सुविधाएं प्रदान कर गुजरात में इनोवेशन संस्कृति को मजबूत बना रही है।

'आई-हब' : गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रमुख केंद्र, करीब 750 स्टार्टअप्स को सीधी सहायता

स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी (एसएसआईपी) के अंतर्गत गठित गुजरात स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब (आई-हब) आज राज्य के इनोवेशन इकोसिस्टम का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। आई-हब राज्य में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कार्यरत सबसे बड़ी सुविधा है, जहां सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम के जरिए कानूनी, वित्तीय और तकनीकी समेत योजना संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से जुड़ा केंद्रीकृत हब स्थापित करके, आई-हब स्टार्टअप्स को प्री-इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन और एक्सलरेशन के चरणों के दौरान उनके आइडियाज, उत्पादन और निवेश की जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करता है।

'आई-हब' की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी, और अब तक इसके अंतर्गत लगभग 750 स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, इनक्यूबेशन सपोर्ट और वित्तीय सहायता दी गई है। स्टार्टअप सृजन सीड सपोर्ट योजना के तहत 400 से अधिक स्टार्टअप्स को 28 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। आई-हब के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स द्वारा राज्य में लगभग 4000 से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। वहीं, इन स्टार्टअप्स का कुल बाजार मूल्य करीब 3569 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

आई-हब के जरिए स्टार्टअप्स को विभिन्न वेंचर फंड्स की ओर से 446 करोड़ रुपए से अधिक का निजी फंड उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही, आई-हब ने 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल के जरिए 20 से अधिक जिलों में अपनी पहुंच का विस्तार किया है और 4.5 लाख से अधिक युवाओं को स्टार्टअप और इनोवेशन के विषय में जागरूक किया है।

'वीस्टार्ट' पहल के तहत 269 महिला संचालित स्टार्टअप्स को सहायता

'वीस्टार्ट', आई-हब द्वारा महिला उद्यमियों के लिए शुरू की गई एक विशेष पहल है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आइडियाज को सफल व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। उल्लेखनीय है कि इस पहल के तहत 269 महिला संचालित स्टार्टअप्स को सहायता दी गई है, जो आई-हब की ओर से समर्थन प्राप्त कुल स्टार्टअप्स का लगभग 36 फीसदी है। इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों को उनके स्टार्टअप के प्रारंभिक चरण के दौरान गति देने और संसाधनों तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल (जीयूएसईसी) की ओर से 'हरस्टार्ट' कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। 'हरस्टार्ट' एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसके चलते अधिक से अधिक महिला उद्यमी अपने आइडियाज को पंख दे रही हैं, और राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना योगदान दे रही हैं।

इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने गुजरात औद्योगिक नीति के तहत भी स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन योजना घोषित की थी, जिसके परिणामस्वरूप अनेक स्टार्टअप्स ने अपने व्यवसाय और उत्पादों का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया है। इस नीति के तहत सीड सपोर्ट ने 471 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की है।

विकसित भारत के अमृत काल में स्टार्टअप्स केवल आर्थिक विकास का साधन ही नहीं, बल्कि नवाचार, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता का एक मजबूत स्तंभ भी है। आज गुजरात का स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्य की सशक्त औद्योगिक परंपरा, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सक्रिय नीतियों और युवा प्रतिभा के समन्वय का एक शानदार उदाहरण बन गया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया: दुर्व्यवहार बंद करो, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाओ मत

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर आपत्तिजनक कार्टून पोस्ट करने के आरोप में एक कार्टूनिस्ट को दंडात्मक कार्रवाई से बचाया। हालांकि, न्यायालय ने सोशल मीडिया पर बढ़ती आपत्तिजनक सामग्री पर चिंता व्यक्त की और इसे रोकने के लिए न्यायिक आदेश जारी करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन रेखा का काम करती है। प्रगतिशील सोच वाले समाज की परिपक्वता का एक संकेत यह है कि वह किसी की राय पर विचार करता है और चाहे तो उसे नजरअंदाज भी कर सकता है। समस्या यह है कि कई बार अभिव्यक्ति को संदेह की नजर से देखा जाता है, इसलिए इसे सीमित करने, यानी इस पर लगाम लगाने के प्रयास किए जाते हैं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज़ हो सकती है, क्योंकि कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने या प्रसारित करने की होड़ लगी हुई है। हाल ही में, कुछ महीने पहले, एक यूट्यूब चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक भाषा, महिला विरोधी टिप्पणियां और विकलांगों का मज़ाक उड़ाने वाली सामग्री प्रसारित की गई, जिसे स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति के अधिकार का दुरुपयोग माना गया। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन तय करेगा और किस आधार पर तय किया जाएगा कि वह अभिव्यक्ति आपत्तिजनक है या नहीं? और फिर भी, अगर अभिव्यक्ति को सीमित करने वाले नियमों और उसके स्वरूप का दुरुपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा?

इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सरकार को अपने फायदे के लिए सच्चाई और तथ्यों को तौलना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यह भी उतना ही सच है कि हमारी सरकारों का नशा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सरकार अपनी ही आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से सरकार अपने आलोचकों को कई तरह से परेशान करती है। इसके कई उदाहरण पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं। अंततः, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकना भी जरूरी है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, इसलिए इस स्वतंत्रता का गला घोंटना भी जरूरी है।

नासिरनगर विध्वंस विवाद: एसएमसी-एसओजी के विरोधाभासी बयानों के बीच लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के वेड दरवाजा के पास नासिर नगर में लगभग 150 मिट्टी की ईंटों से बने मकानों को गुपचुप तरीके से गिराए जाने से एसएमसी और एसओजी (नगर निगम) की नींद उड़ गई है। इस विध्वंस मामले में, जिसमें नगर निगम की टीम अब तक कहती आ रही थी कि विध्वंस कार्य में उनकी कोई भूमिका नहीं है, बारह साल और बारह दिन बाद जोनल प्रमुख आशीष नायक ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सूरत नगर निगम द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से कानूनी बताया जा रहा है। वहीं, सूरत नगर निगम के उपायुक्त एम. नागरजन ने 11/06/2026 की शाम पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि विध्वंस किसने किया, यह जांच का विषय है। आयुक्त नागरजन ने कहा कि विध्वंस, पुलिस व्यवस्था और अन्य सवालों के जवाब में यह जांच की जा रही है। विभाग के उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ क्या जांच होनी चाहिए जिनके खिलाफ शिकायत है? ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस पूरी घटना में किसी भी तरह की अवैध तोड़फोड़ नहीं हुई थी, तो तोड़फोड़ के समय इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? और उन्होंने बारह दिनों तक शुतुरमुर्ग की तरह अपना चेहरा क्यों छिपाया और मीडियाकर्मियों से क्यों भागते रहे?

तो यहाँ मुख्य बात यह है कि एसएमसी और एसओजी पर लगे आरोपों के चलते, जोनल चीफ, जिन्हें ऊपर से इशारों-इशारों में जानकारी दी गई थी, को यह बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि तोड़फोड़ नगर निगम द्वारा की गई थी। ऐसे में केंद्रीय जोन का कौन सा अधिकारी सच बोल रहा है और कौन अपराधियों को बचा रहा है? इस पर भी संदेह पैदा हो रहा है। साथ ही, मीडिया पर भी पूरी तोड़फोड़ की घटना को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लग रहा है।

दरअसल, नासिर नगर के पास स्थित निजी परियोजना के लाभ के लिए, नियमों और नीतियों की अनदेखी करते हुए, बिल्डर के हित में नगरपालिका अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ का काम किए जाने के आरोपों के बाद भारी हंगामा हुआ। नगर निगम का कहना है कि उनकी टीम सड़क का सीमांकन और उसे खोलने के लिए पहुंची थी। यह काम नगरपालिका के नियमों और नीतियों के तहत किया गया था और नगर निगम ने इस संबंध में जो कहा, उससे वह हैरान है। जब मीडिया स्पष्टीकरण के लिए नगर आयुक्त एम. नागराजन से पूछने गया, तो मीडिया के कैमरे देखकर नगर आयुक्त और इंजीनियर आशीष नायक भाग गए और सम्मेलन कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया। जब मीडिया ने हॉल में प्रवेश करने की कोशिश की, तो मार्शल और पुलिस ने मीडिया को रोककर लाठियों से पीटा। यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है।

एक साल बाद भी अनसुलझे सवाल: अहमदाबाद विमान हादसे की जांच कहां तक पहुंची, क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ और इकलौते जीवित बचे यात्री?

नई दिल्ली। देश के सबसे दर्दनाक विमान हादसों में गिने जाने वाले अहमदाबाद विमान दुर्घटना को एक वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन इस हादसे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। पिछले वर्ष 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। विमान में सवार 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 241 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जमीन पर भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कुल मिलाकर इस भीषण हादसे में 260 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह दुर्घटना केवल एक विमान हादसा नहीं थी, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों, उम्मीदों और जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाली त्रासदी बन गई।

हादसे के एक वर्ष बाद भी इसकी जांच जारी है और देश-विदेश की विमानन एजेंसियां दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हाल ही में जानकारी दी कि जांच प्रक्रिया पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और पेशेवर मानकों के तहत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमानन नियमों का पालन करते हुए विशेषज्ञों की टीम हर पहलू का गहन अध्ययन कर रही है। दुर्घटना के पीछे तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि, मौसम संबंधी परिस्थितियां या अन्य संभावित कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल दुर्घटना के कारणों की पहचान करना नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा सुधारों को लागू करना भी है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद उसके निष्कर्षों के आधार पर विमानन सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार और विमानन क्षेत्र से जुड़े सभी संस्थान

इस मामले को अत्यंत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ देख रहे हैं। दुर्घटना की जांच भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा की जा रही है। जांच एजेंसियों ने विमान के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और अन्य तकनीकी उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त विमान के रखरखाव रिकॉर्ड, उड़ान संचालन संबंधी दस्तावेज, मौसम संबंधी रिपोर्ट और चालक दल के प्रशिक्षण रिकॉर्ड की भी समीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े विमान हादसे की जांच एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि प्रत्येक तथ्य और तकनीकी संकेत की पुष्टि करना आवश्यक होता है।

इस मामले में विमान निर्माता कंपनी बोइंग भी जांच में सहयोग कर रही है। हादसे की पहली बरसी पर कंपनी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अपने आधिकारिक बयान में बोइंग ने कहा कि वह जांच एजेंसियों को हर संभव तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में पूर्ण सहयोग देगी। कंपनी ने यह भी दोहराया कि विमानन सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और वह जांच प्रक्रिया के निष्कर्षों का सम्मान करेगी।

हादसे का वह दिन आज भी लोगों की स्मृतियों में ताजा है। विमान ने उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद नियंत्रण खो दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान तेजी से नीचे आया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विस्फोट और आग की लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। बचाव दल, दमकलकर्मी और स्थानीय प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। दुर्घटनास्थल पर चारों ओर मलबा, धुआं और तबाही का भयावह दृश्य दिखाई दे रहा था। इस भीषण त्रासदी के बीच एक नाम ऐसा था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा—विश्वास कुमार रमेश। विमान में सवार यात्रियों में वे अकेले व्यक्ति थे जो जीवित बच पाए। शुरुआत में जब उनके जीवित होने की खबर सामने आई तो लोगों को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। अनेक लोगों ने इसे चमत्कार बताया। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि जीवन बच जाना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ था।

विश्वास कुमार रमेश आज भी उस हादसे की यादों के साथ जी रहे हैं। शारीरिक रूप से बच जाने के बावजूद मानसिक और भावनात्मक स्तर पर वे गहरे आघात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कई अवसरों पर बताया है कि दुर्घटना की भयावह स्मृतियां उनका पीछा नहीं छोड़तीं। रात में नींद न आना, अचानक घबराहट महसूस होना, दुर्घटना के दृश्य बार-बार आंखों के सामने आ जाना और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं आज भी उनके जीवन का हिस्सा हैं।

विशेषज्ञ बताते हैं कि किसी बड़ी दुर्घटना से जीवित बचने वाले लोगों में पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसी मानसिक स्थितियां विकसित होना सामान्य बात है। ऐसे लोग अक्सर लंबे समय तक भय, चिंता, अवसाद और मानसिक असुरक्षा से जूझते हैं। विश्वास कुमार रमेश के मामले में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। उनके अनुसार कई बार सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने के बावजूद दुर्घटना की यादें अचानक सामने आ जाती हैं और उन्हें मानसिक रूप से विचलित कर देती हैं।

हादसे के बाद उनके जीवन में एक और चुनौती सामने आई। वे लगातार लोगों की जिज्ञासा और मीडिया के ध्यान का केंद्र बने रहे। हर कोई जानना चाहता था कि वे आखिर कैसे बच गए। लेकिन इस चर्चा के पीछे छिपे उनके मानसिक संघर्ष को बहुत कम लोग समझ पाए। उन्होंने स्वीकार किया है कि जीवित बचना उनके लिए राहत जरूर था, लेकिन इसके बाद शुरू हुई मानसिक लड़ाई कहीं अधिक कठिन साबित हुई।

विमान दुर्घटनाओं के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं के बाद केवल तकनीकी जांच ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि पीड़ित परिवारों और जीवित बचे लोगों के मानसिक पुनर्वास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। कई देशों में बड़े हादसों के बाद दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि प्रभावित लोग सामान्य जीवन में लौट सकें। भारत में भी अब इस दिशा में अधिक जागरूकता देखने को मिल रही है।

'विकसित पोरबंदर' की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम

पोरबंदर में वर्ल्ड क्लास फर्नीचर पार्क के विकास के लिए उद्योग जगत के साथ आयोजित होगी उच्च स्तरीय समिट

गांधीनगर, 12 जून : पोरबंदर को वैश्विक स्तर के फर्नीचर उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में आगामी 13 जून, 2026 को 'विकसित पोरबंदर फर्नीचर पार्क समिट' का आयोजन किया गया है। इस समिट के अंतर्गत पोरबंदर में प्रस्तावित मेगा फर्नीचर पार्क की स्थापना की संभावनओं, उसके विकास के लिए मार्गदर्शन एवं भविष्य की रणनीतिक कवायद के विषय में उद्योग जगत के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।

इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री एवं पोरबंदर के सांसद डॉ. मनसुख मांडविया और गुजरात सरकार के मंत्री एवं पोरबंदर के विधायक श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया की प्रेरक उपस्थिति में हितधारकों के साथ संवाद आयोजित होगा। पोरबंदर में औद्योगिक विकास तथा आने वाले समय में औद्योगिक रूपरेखा के विस्तार के लिए यह समिट एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होगी।

देशभर के फर्चनीर उद्योग जगत के अग्रणी होंगे सहभागी

फर्नीचर उत्पादन तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के उद्योगपतियों, उद्योग संगठनों व व्यापारिक मंडलों के प्रतिनिधियों सहित राज्यभर से 50 से अधिक प्रतिनिधियों को इस समिट में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा; विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा प्रतिष्ठित ब्रांड्स के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रहेगी; जिनमें अहमदाबाद स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग, IKEA, Dato Sanso, Hettich, Merino, Royal Touch Laminates, Medoc और Aemor सहित गुजरात टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, गुजरात टिम्पर ऑक्शन एसोसिएशन, गुजरात ग्रीन इकोनॉमिक चैम्बर तथा पोरबंदर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहने वाले हैं।

विभिन्न सरकारी विभागों की भागीदारी

फर्नीचर पार्क की संभावित स्थापना के लिए आवश्यक एकीकृत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार के उद्योग विभाग, बंदरगाह विभाग सहित स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों के उच्चाधिकारी भी इस समिट में भाग लेंगे और आवश्यक रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय साधकर भावी कार्यवाही के लिए मार्गदर्शक चर्चा की जाएगी।

स्थल निरीक्षण तथा स्थानीय व्यवस्था

समिट में भाग लेने आने वाले देश-विदेश के प्रतिनिधि 14 जून, 2026 को पोरबंदर में फर्नीचर पार्क के लिए प्रस्तावित स्थलों का दौरा भी करेंगे। पोरबंदर के निकट स्थित भारवाडा में इस पार्क निरीक्षण द्वारा प्रोजेक्ट की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और स्थानीय स्तर पर जिन ढाँचागत सुविधाओं का विकास किए जाने की जरूरत है, उस संबंध में अवलोकन किया जाएगा।

इस अवसर पर पोरबंदर के विशिष्ट आतिथ्य तथा सौराष्ट्र की कला-संस्कृति का परिचय कराने के लिए प्रशासन द्वारा प्रतिनिधियों के स्वागत एवं आवश्यक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है।

पोरबंदर के औद्योगिक भविष्य के लिए आशावादी पहल

'विकसित पोरबंदर फर्नीचर पार्क समिट' केवल एक बैठक नहीं, बल्कि पोरबंदर को नए औद्योगिक आयामों की ओर ले जाने वाली दृष्टिपूर्ण पहल है। आशा व्यक्त की जा रही है कि यह समिट फर्नीचर क्षेत्र में निवेश, रोजगार के नए अवसर, स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन इकोसिस्टम के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सकती है।

दिनांक 13 व 14 जून, 2026 को आयोजित होने वाली यह समिट पोरबंदर के विकास के नए अध्याय के प्रारंभ समान बन सकती है, जहाँ स्थानीय संभावनाओं को वैश्विक अवसरों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

मौत से मुकाबला: सातवीं मंजिल पर फंसे युवक को पुलिस ने दिखाई जिंदगी की राह

सूरत। गुजरात के सूरत शहर में पुलिस की बहादुरी, तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का एक ऐसा उदाहरण सामने आया है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। सातवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में खुद को बंद कर चुके और जहरीला पदार्थ खा चुके युवक की जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जोखिम उठाया और समय रहते उसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर एक बड़ी अनहोनी टाल दी। इस साहसिक कार्रवाई की पूरे शहर में चर्चा हो रही है और स्थानीय लोग पुलिसकर्मियों की जमकर सराहना कर रहे हैं।

घटना सूरत के लसकाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक ने कथित रूप से जहरीली दवा का सेवन कर लिया और उसके बाद अपने फ्लैट के अंदर खुद को बंद कर लिया। स्थिति की गंभीरता तब सामने आई जब इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंची। जानकारी मिलते ही लसकाना पुलिस की पीसीआर-81 टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी किरणभाई और कृपाल सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना किसी देरी के घटनास्थल की ओर रुख किया।

मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने पाया कि युवक सातवीं मंजिल पर स्थित अपने

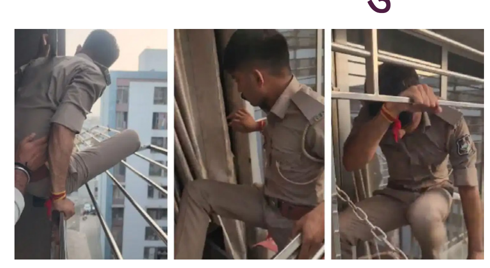

फ्लैट में बंद था और उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण सामान्य तरीके से उसके पास पहुंचना संभव नहीं था। समय बीतने के साथ युवक की जान को खतरा बढ़ता जा रहा था। ऐसे में पुलिसकर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी भी तरह युवक तक पहुंचा जाए और उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए।

स्थिति का आकलन करने के बाद पुलिसकर्मियों ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने पड़ोसी इमारत की बालकनी के रास्ते युवक तक पहुंचने का फैसला किया। यह फैसला जितना आसान सुनने में लगता है, वास्तव में उतना ही जोखिम भरा था। सातवीं मंजिल की ऊंचाई पर जरा सी चूक भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। लेकिन युवक की जान बचाने के संकल्प ने पुलिसकर्मियों को पीछे हटने का अवसर नहीं दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिसकर्मियों ने बिना अपनी सुरक्षा की चिंता किए पड़ोसी इमारत की बालकनी से होते हुए युवक के फ्लैट तक पहुंचने का जोखिम उठाया। ऊंचाई पर संतुलन बनाए रखते हुए उन्होंने बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ युवक तक पहुंच बनाई। वहां पहुंचने पर उन्होंने युवक को संभाला और सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आसपास मौजूद लोगों की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि किसी भी क्षण स्थिति गंभीर रूप ले सकती थी।

युवक को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने समय गंवाए बिना उसे पीसीआर वाहन के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार यदि उपचार में थोड़ी भी देरी होती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। समय पर अस्पताल पहुंचाए जाने के कारण युवक को आवश्यक चिकित्सा सहायता मिल सकी और उसकी जान बच गई। इलाज के बाद जब युवक को होश आया तो उसके परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार व्यक्त किया।

इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने का ही कार्य नहीं करती, बल्कि कई बार लोगों की जान बचाने के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाल देती है। किरणभाई और कृपाल सिंह की बहादुरी ने यह दिखा दिया कि कर्तव्यनिष्ठा और मानवता का भाव किसी भी चुनौती से बड़ा होता है। दोनों पुलिसकर्मियों ने जिस साहस और जिम्मेदारी का परिचय दिया, वह समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है।

घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस टीम की खुलकर प्रशंसा की। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंचती और इतना साहसिक कदम नहीं उठाती, तो परिणाम बेहद दुखद हो सकते थे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी पुलिसकर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें वास्तविक नायक बताया है। युवक के परिजनों ने भी भावुक होकर पुलिस का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों की तत्परता और साहस की वजह से उनके परिवार का एक सदस्य आज जीवित है। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करते हैं।

यह घटना केवल एक बचाव अभियान नहीं थी, बल्कि मानव जीवन के प्रति समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल भी थी।